राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष – 03 | अंक – 306 | जौनपुर | गुरूवार, 26 जून 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

भवन के अलावा जमीन का भी मिलेगा मुआवजा, योगी के निर्देश पर मंथन शुरू

गोरखपुर, (संवाददाता)। विरासत गलियारा में सड़क चौड़ीकरण के दौरान जो मकान टूट रहे हैं और उनके मालिकों के पास जमीन का कागजात नहीं था, अब उन्हें भी कब्जे के आधार पर मुआवजा दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व विभाग अब इसके लिए कानूनी उपाय खोज रहा है। इस पर चर्चा के लिए मंगलवार को अफसरों, भाजपा नेताओं, स्थानीय दुकानदारों और घर मालिकों के बीच बैठक भी हुई। पांडेय हाता से घंटाघर, आर्यनगर होते हुए ध र्मशाला ओवरब्रिज के पास तक सड़क को विरासत गलियारा के रूप में विकसित किया जा रहा है। चौड़ीकरण की जद में आ रहे मकान और दुकानों की रजिस्ट्री लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हो रही है।

संक्षिप्त खबरें

सोनम और राज कुशवाह ने प्रेम संबंध होने की बात स्वीकारी

शिलांग, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या होने के मामले में आरोपी उनकी पत्नी सोनम और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाह ने पुलिस पूछताछ में प्रेम संबंध की बात स्वीकार कर ली है। दोनों ने राजा की हत्या में अपनी भूमिका भी स्वीकार कर ली है। मेघायल पुलिस ने बुधवार को यह खुलासा किया है। पुलिस अब मामले में दोनों के वित्तिय लाभ होने की भूमिका की भी जांच कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, मेघालय पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विवेक सायम बताया कि सोनम और राज दोनों ने अपने प्रेम संबंध और राजा की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि राज के साथ उसके रिश्ते से नाखुश सोनम के परिवार ने उसकी शादी राजा से तय की थी। इससे नाराज सोनम ने परिवार को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उसकी शादी राजा से करवाई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एसपी सायम ने बताया कि सोनम और राज का प्रेम–प्रसंग अभी भी हत्या के पीछे मुख्य कारण है, लेकिन पुलिस वित्तीय लाभ जैसे अन्य उद्देश्यों की भी जांच की जा रही है। हालांकि वे अभी तक पुख्ता तौर पर स्थापित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोनम और राज अपने प्रेम संबंध के चलते ही राजा को बीच से हटाना चाहते थे। सोनम ने मजबूरी में शादी की थी इसलिए राजा की हत्या ही एकमात्र रास्ता था। सायम ने बताया कि राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कार नहर में गिरने से नवजात समेत 4 लोगों की मौत

हल्द्वान, (एजेंसी)। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बुधवार को भारी बारिश के बीच 7 लोगों से भरी एक कार सड़क से उतरकर उफनती नहर में गिर गई, जिससे 4 दिन के नवजाता शिशु सहित 4 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह कार सवार 3 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को नहर से निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों के परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार, किच्छा के बरा निवासी महिला को 4 दिन पहले प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लाया गया था, जहां उसने बेटे को जन्म दिया था। बुधवार को छुट्टी मिलने पर परिवार दोनों को कार से वन विभाग के बगल में रही नहर के रास्ते किच्छा जा रहा था। भारी बारिश के बीच मोड़ पर चालक के नियंत्रण खो देने से कार नजर में जा गिरी। इस हादसे में नवजात, उसके पिता, नानी और ताऊ की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे की सूचना पर दमकल टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर कार और उसमें सवार लोगों को बाहर निकाला और घायल हुए चालक, नवजात की मां समेत 3 को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सूचना कर दी है। उनके आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी।

मोदी राज में किसानों में आई खुशहाली, अब किसान आत्महत्या नहीं करता है : सीएम योगी

लखनऊ, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों की अकर्मण्यता के कारण कृषि के क्षेत्र में जो विकास हो सकता था वो नहीं हो पाया। इससे हमारे किसान लाभ से वंचित रह गए। योजनाएं आपस में धन के बंदरबांट के लिए बनती थीं और हमारे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता था। 2014 में केंद्र में प्रध ानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में समग्र विकास की जो अवध ारणा विकसित हुई है। उससे देश का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ में गोरखपुर, कानपुर एवं कन्नौज के डेयरी प्लांट्स तथा अंबेडकरनगर की पशु आहार निर्माणशाला के संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के मध्य एमओयू कार्यक्रम को संबोधि त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समग्र विकास के परिणाम स्वरूप अब किसानों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अब अन्नदाता किसान खुशहाल है। आत्महत्या नहीं करता है। आज उसे कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य सेक्टरों में बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। तकनीक भी मिलती है और सरकार हर प्रकार से उसे सहयोग करने के लिए तत्पर भी रहती है। इस मौके पर योगी ने कई प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। गेहूं, धान, चना, सरसो, मक्का, अरहर, उरद और तिल का सर्वाधिक उत्पादन करने वालों को उन्होंने सम्मान दिया।

उत्तराखंड पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया स्वागत

हल्द्वानी, (एजेंसी)। देश के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने तीन दिवसीय उत्तराखंड भ्रमण पर नैनीताल जिले के हल्द्वानी पहुंचे. हल्द्वानी आर्मी हेलीपैड पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया. राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, सांसद अजय भट्ट, मेयर हल्द्वानी गजराज बिष्ट में भी उनका स्वागत किया. बुधवार को हल्द्वानी आर्मी हेलीपैड पहुंचे पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राज्यपाल ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया. इसके बाद उपराष्ट्रपति ने मौजूद सेना के जवानों से मुलाकात की. इसके बाद उपराष्ट्रपति भारी सुरक्षा के बीच बॉय रोड नैनीताल राजभवन पहुंचे. वहीं अपने तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति आज 25 जून को कुमाऊं विश्वविद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम के अलावा अन्य समारोह में भी प्रतिभा करेंगे. साथ ही कुमाऊं विश्वविद्यालय की फैकल्टी के साथ संवाद भी करेंगे. जबकि उपराष्ट्रपति का 27 जून को नैनीताल के शेखुड कॉलेज में विद्यार्थियों को संबोधित कार्यक्रम भी है. ।

पीएम मोदी की अध्यक्षता पर लिया गया संकल्प

नई दिल्ली, (एजेंसी)। इमरजेंसी की घोषणा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन अनगिनत व्यक्तियों के बलिदान को याद करने और उनका सम्मान करने का संकल्प लिया, जिन्होंने आपातकाल और भारतीय संविधान की भावना को नष्ट करने के उसके प्रयास का बहादुरी से विरोध किया था। इसमें कहा गया कि एक विध्वंस जो

1974 में नवनिर्माण आंदोलन और संपूर्ण क्रांति अभियान को कुचलने के एक कठोर प्रयास के साथ शुरू हुआ था। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार की बैठक में उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में दो मिनट का मौन रखा गया जिन्होंने इमरजेंसी में संवैधानिक रूप से गारंटीकृत लोकतांत्रिक अधिकार गंवा दिए थे। ऐसे में उन लोगों को तब अकल्पनीय भयावहता का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकाल की ज्यादतियों के खिलाफ उनके अनुकरणीय साहस और बहादुरीपूर्ण प्रतिरोध को श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्तावों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया आज कैबिनेट बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए। रेल मंत्री ने कहा कि इसमें पुणे मेट्रो विस्तार के लिए 3626 करोड़ रुपये पारित किए गए। दूसरा झरिया (झारखंड) भूमिगत आग का बहुत पुराना मुद्दा है। इसके लिए 5940 करोड़ रुपये का संशोधित मास्टर प्लान मंजूर किया गया। वहीं, तीसरा फैसला आगरा में 111 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने का लिया गया।

सरकार ने सशस्त्र बलों के बीच अधिक अंतर-संचालन और जॉइंटनेस लाने की दिशा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सरकार ने सशस्त्र बलों के बीच अधिक अंतर–संचालन और जॉइंटनेस लाने की दिशा में एक और कदम उठाया। इसके लिए सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अधिकार में बढ़ोतरी की है। सरकार के नए फैसले के बाद अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) को तीनों सशस्त्र बलों को संयुक्त निर्देश और आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। खास बात है कि यह कद अतीत से अलग है। पहले प्रत्येक सर्विसेज – आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के लिए अलग–अलग आदेश जारी होता था। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस को बढ़ी हुई शक्तियां दीं। इसके बाद पहला संयुक्त आदेश मंगलवार को जारी किया गया। संयुक्त निर्देशों और संयुक्त आदेशों के अनुमोदन, प्रख्यापन और क्रमांकन पर पहला आदेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, अतिरेक को खत्म करने और क्रॉस–सर्विस सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर केंद्रित है। अधिकारियों ने कहा कि यह पहल तीनों सेनाओं में बेहतर पारदर्शिता, समन्वय और प्रशासनिक दक्षता की नींव रखती है। यह एकजुटता और एकीकरण के एक नए युग की शुरुआत भी है। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस

स्टाफका पद 2019 में सृजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य तीनों सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना, और वायु सेना) के बीच समन्वय को बढ़ाना, रक्षा नीतियों को एकीकृत करना, और सैन्य सुधारों को लागू करना था। इसकी सिफारिश 1999 के कारगिल युद्ध के बाद कारगिल समीक्षा समिति द्वारा की गई थी। रक्षा मंत्री और सरकार के लिए प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वह रक्षा मामलों में एकल बिंदु संपर्क प्रदान करता है। थिएटर कमांड की स्थापना के साथ ही उसके कार्यान्वयन में सीडीएस की भूमिका काफी अहम है।

कब हुई संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए शाह ने कहा कि यह दिन सभी को याद दिलाता है कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है, तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। गृह मंत्री अमित शाह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संदर्भ में कहा कि आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं, बल्कि कांग्रेस और एक व्यक्ति की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था। गृह मंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया था। आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का 'अन्यायकाल' था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान देशवासियों ने जो पीड़ा और

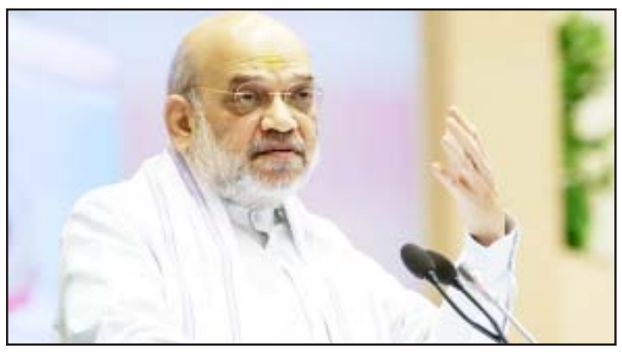

यातना सही, उसे नई पीढ़ी जान सके, इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने इस दिन को 'संविधान हत्या दिवस' का नाम दिया। शाह ने 'एक्स' पर लिखा, "आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं, बल्कि कांग्रेस और एक व्यक्ति की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था। गृहमंत्री शाह ने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई, न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। उन्होंने इस संघर्ष में बलिदान देने वाले सभी वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि "देशवासियों ने 'सिंहासन खाली करो' का शंखनाद किया और तानाशाह कांग्रेस को उखाड़ फेंका। पिछले साल शाह ने घोषणा की थी कि मोदी सरकार 25 जून को श्संविधान हत्या दिवसश के रूप में मनाएगी, ताकि इस अवधि के दौरान श्अमानवीय पीड़ाश सहने वालों के श्बड़े योगदानश को याद किया जा सके। उन्होंने इसकी घोषणा करते वक्त कहा था कि श्संविधान हत्या दिवसश मनाने से प्रत्येक भारतीय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता व लोकतंत्र की रक्षा की अमर ज्वाला को प्रज्वलित रखने में मदद मिलेगी, जिससे कांग्रेस जैसी श्तानाशाही ताकतोंश को श्उन भयावहताओं को दोहरानेश से रोका जा सकेगा।

महाराष्ट्र में हिंदी पहली से नहीं बल्कि पांचवीं कक्षा से पढ़ाई जानी चाहिए : अजित पवार

मुबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य के विद्यालयों में पहली कक्षा से तीसरी के रूप में हिंदी को शामिल किए जाने के कदम का विरोध किया और कहा कि इसे पांचवीं कक्षा से पढ़ाया जाना चाहिए। मंगलवार को मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने यह भी कहा कि छात्रों को पहली कक्षा से ही मराठी सीखनी चाहिए ताकि वे इसे अच्छी तरह से पढ़ और लिख सकें। राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह एक संशोधित आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहली से पांचवी कक्षा तक के विद्यार्थियों को हिंदी सामान्यतः तीसरी के रूप में पढ़ाई जाएगी, जिसके बाद इस पर विवाद पैदा हो गया। सरकार ने कहा कि हिंदी अनिवार्य नहीं होगी तथापि उसने हिंदी के अलावा किसी अन्य का अध ययन करने के लिए स्कूल में प्रत्येक कक्षा में कम से कम 20 छात्रों की सहमति अनिवार्य कर दी। पवार ने कहा, ''मुख्यमंत्री ने सोमवार को इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाई। मेरा मानना है कि हिंदी को पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक शुरू नहीं किया जाना चाहिए। इसे पांचवीं कक्षा से शुरू किया जाना चाहिए। छात्रों को पहली कक्षा से मराठी सीखनी चाहिए और इसे ध ाराप्रवाह पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि कोई भी किसी विशेष को पढ़ाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन युवा छात्रों पर शुरुआती चरण में एक अतिरिक्त का बोझ डालना अनुचित है। इस बीच, अभिनेता सयाजी शिंदे ने भी पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने का विरोध किया। उन्होंने कहा, ''छात्रों को मराठी सीखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो एक बहुत ही समृद्ध है। उन्हें कम उम्र में ही मराठी में पारंगत होना चाहिए और उन पर किसी अन्य का बोझ नहीं डालना चाहिए। अगर इसे अनिवार्य बनाना ही है, तो इसे पांचवीं कक्षा के बाद ही पढ़ाया जाना चाहिए।

जगन ने आंध्र सरकार पर छात्रों, बेरोजगार युवाओं की मदद नहीं करने का आरोप लगाया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। वाईएसआरसीपी के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम

पार्टी (तेदेपा) के नेतृत्व वाली गठबंध न सरकार पर युवाओं और छात्रों को धोखा देने का आरोप लगाया है। रेड्डी ने बेरोजगारी भत्ते के वादे को कथित रूप से पूरा नहीं करने के खिलाफ सोमवार को अपनी पार्टी के नेतृत्व में आयोजित राज्यव्यापी युवा पोरु (युवा संघर्ष) प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने मंगलवार को कहा कि सरकार नौकरी और शिक्षा सहायता जैसे अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पलनाडु जिले के नरसारावपेटा शहर में प्रदर्शनकारियों को तितर–बितर करने के लिए की गई पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "नरसारावपेट में छात्रों पर लाठीचार्ज ने सरकार के हिंसक, असहिष्णु रवैये को उजागर किया है।" पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान तेदेपा द्वारा किए गए वादे के अनुसार 3,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ते के कार्यान्वयन के लिए केवल ज्ञापन प्रस्तुत करने और इस बारे में पूछने पर छात्रों पर कथित रूप से हमला क्यों किया गया। रेड्डी ने कहा कि राज्य के 1.25 करोड़ बेरोजगार युवाओं में से कितनों को भत्ता मिला। वाईएसआरसीपी प्रमुख ने आरोप लगाया ।

स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला दिन : सीएम नीतीश

पटना, (एजेंसी)। आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए। इस दौरान देश की सत्ता लेकर सियासत तक में बहुत कुछ बदल गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर आपातकाल को लेकर भावनात्मक पोस्ट किया। उन्होंने इसे तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की तानाशाही का प्रतीक बताया। सीएम नीतीश ने बताया कि आपातकाल में जनता की अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगा दी गई थी। हम सभी साथियों को तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जेल में बंद कर दिया गया था। बिहार ने हमेशा संविधान, न्याय, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की भावना को अपने विकास का मार्ग बनाया है। हम संविधान के आदर्शों की रक्षा के लिए सदैव सजग एवं तत्पर रहेंगे। देश में आपातकाल के 50 साल हो गए।

25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस दौर को याद करते हुए अपनी बात रखी। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म र पर अपनी यादें साझा कीं। उन्होंने लिखा, श्25 जून 1975 का वो दिन हम सभी को याद है, जब देश में आपातकाल लागू हुआ था। इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला दिन कहा जाता है। साल 1975 का आपातकाल तत्कालीन सरकार की तानाशाही का प्रतीक था। आपातकाल में जनता की अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगा दी गई थी।श सीएम नीतीश ने अपने आगे लिखा, श्आपातकाल के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन शुरू किया। मैंने भी अपने कई साथियों के साथ इस आंदोलन में भाग लिया तथा आपातकाल का सक्रिय विरोध किया। हम सभी साथियों को तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन, देशवासियों ने एकता और साहस का परिचय दिया। एकजुट होकर हमने लड़ाई लड़ी। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, श्आप सभी को पता है कि लोकतंत्र के मूल में जनता की आवाज होती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करें। बिहार ने हमेशा संविधान, न्याय, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की भावना को अपने विकास का मार्ग बनाया है। हमारा ये संकल्प रहे कि हम संविधान के आदर्शों की रक्षा के लिए सदैव सजग एवं तत्पर रहेंगे। दरअसल, 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लागू हुई थी। इसे देश के इतिहास का काला दिन माना जाता है। इस घटना के 50 साल पूरे हो चुके हैं।

संपादकीय

बेटियां संवेदनशील

देशकाल–परिस्थितियों और बदलती जरूरतों के अनुरूप वैश्विक स्तर पर एक सूक्ष्म, लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव दृष्टिगोचर हो रहा है। यह बदलाव लिंग प्राथमिकताओं को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण में आ रहे परिवर्तन का है। जैसा कि हाल ही में 'द इकनॉमिस्ट' द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़कों के प्रति सदियों पुराना झुकाव अब कम हो रहा है। दुनियाभर में, अतिरिक्त पुरुष जन्म की संख्या– जो वर्ष 2000 में 1.7 मिलियन तक अधिक थी, साल 2025 तक लगभग दो लाख तक गिर गई है। निस्संदेह, यह प्रजनन विकल्पों में एक अप्रत्याशित बदलावों का संकेत है। यहां तक कि दक्षिण कोरिया और चीन में, लिंग अनुपात सामान्य या यहां तक कि बेटी की पसंद के संकेत दिखाने लगा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस बदलाव की असल वजह क्या है३ दरअसल, माता–पिता में यह धारणा बलवती होती जा रही है कि बेटियां उनकी ढलती उम्र में धीरे–धीरे अधिक विश्वसनीय देखभाल करने वाली साबित हो सकती हैं। उन्हें परिवार से गहरे तक जुड़े रहने की अधिक संभावना के रूप में देखा जाने लगा है। आज बेटियों को बेटों के मुकाबले बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शनकर्ता के रूप में देखा जा सकता है। तेजी से कामकाजी दुनिया का हिस्सा बनने के कारण वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती जा रही है। बल्कि कई देशों में तो महिलाओं की बेचलर डिग्री की संख्या तक पुरुषों की तुलना में अधिक है। पश्चिमी देशों में गोद लेने और आईवीएफ के डेटा दिखाते हैं कि बेटियों को चुनने की दिशा में स्पष्ट झुकाव है। दरअसल, पश्चिमी देशों के एकल परिवारों में बेटे अपनी गृहस्थी बसाकर मां–बाप को उनके भाग्य पर छोड़ जाते हैं। ऐसा माना जाने लगा है कि बेटियां बेटों के मुकाबले में ज्यादा संवेदनशील होती हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव में मां–बाप को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकती हैं। जिसके चलते लोग बेटों के मुकाबले बेटियों को अपनी प्राथमिकता बनाने को तरजीह देने लगे हैं। वहीं भारत में परिस्थितियां एक जटिल तसवीर प्रस्तुत करती हैं। यूं तो सदियों से भारत का समाज पुत्र मोह की ग्रंथि से ग्रस्त रहा है। हालांकि, अब आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि देश में शिशु लिंग अनुपात दर में सुधार हुआ है। लेकिन लिंग चयन के लिये किए जाने वाले गर्भपात पर शासन व प्रशासन की कानूनी सख्ती और जागरूकता अभियानों के बावजूद परंपरागत रूप से समाज में गहरी जड़ें जमाने वाला बेटा मोह अब भी प्राथमिकता बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5(2019–21) का सर्वे चिंता बढ़ाने वाला है। सर्वे के अनुसार, लगभग 15 फीसदी भारतीय माता–पिता अभी भी बेटियों की तुलना में बेटों की आकांक्षा रखते हैं। यही वजह है कि हरियाणा,पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विषम शिशु लिंगानुपात चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा, भारत में बेटी वरीयता, जहां यह मौजूद है, अक्सर सशर्त होती है। लड़कियों को भावनात्मक लगाव या घरेलू स्थिरता के लिये तो महत्व दिया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पोषण, शिक्षा या विरासत तक उन्हें समान पहुंच दी जाए। भारतीय समाज में दहेज जैसी सांस्कृतिक प्रथाएं आज भी बेटी के माता–पिता की बड़ी चिंता बनी रहती हैं।

ट्रंप के दावों के बावजूद रुकेगा नहीं ईरान

पुष्परंजन

आप ईरान के ठिकानों पर कोऑर्डिनेटेड बमबारी करें, फिर घोषणा कर दें, कि इस्राइल–ईरान युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। यह अमेरिकी दादागिरी का दीगर रूप है। खुद की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, 'ट्रुथ सोशल' पर डोनाल्ड ट्रम्प बोले, 'यदि ईरान के पास परमाणु हथियार है, तो आप शांति नहीं पा सकते।' ऐसे बोल–वचन इसलिए, ताकि पश्चिमी देश खुश हो जाएं। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई अपरिहार्य और नैतिक रूप से उचित साबित हो। ये वही ट्रम्प हैं, जो बात–बात पर परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में दावत देते हैं। लेकिन, तो ताचश्म पाकिस्तान ने बयान दिया, कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अगर, परमाणु क्षमता का आकांक्षी ईरान शांति का दुश्मन है, तो अमेरिका के पास लगभग 5,244 परमाणु हथियार हैं, जो कि इस्राइल के अघोषित शस्त्रागार में अनुमानित संख्या से दस गुना अधिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अधिकरण (आईएइए) खुफिया के अनुसार, 'ईरान ने अभी तक परमाणु हथियार नहीं बनाया है।' ईरान परमाणु हथियारों के अप्रसार (एनपीटी) पर संधि का हस्ताक्षरकर्ता बना हुआ है। इजरायल नहीं है। अमेरिका के पास 100 से अधिक देशों में 800 से अधिक सैन्य अड्डे हैं। इसकी तुलना चीन से करें, जो पड़ोसी क्षेत्रों में केवल एक विदेशी सैन्य अड्डे रखता है, या रूस, जो लगभग बीस सैन्य अड्डों का प्रबंधन करता है। यह वैश्विक स्थिरता का संकेत नहीं है। यह एक साम्राज्यवादी ढब है। पूरी दुनिया का चौधरी बने रहने की लिप्सा। विदेश संबंध परिषद के अनुसार, 'इस समय मध्य पूर्व में कम से कम 19 अमेरिकी मिलिटरी बेस हैं। इनमें से आठ स्थायी सैन्य ठिकाने हैं।' बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में बनाए अमेरिकी सैन्य ठिकाने हटवाने की हिम्मत वहां की कठपुतली सरकारें नहीं करतीं। अमेरिका ने पूरे मिडल ईस्ट में लगभग 40,000 सैनिक

तैनात किये हैं। कतर में 1996 में निर्मित अल उदीद एयरबेस मध्य पूर्व का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। यह ईरान द्वारा लक्षित स्थलों में से एक था। इस बेस पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का क्षेत्रीय मुख्यालय है, जहां 11,000 से अधिक अमेरिकी और गठबंधन सेना के सदस्य रहते हैं। यहां जो कुछ ईरानी हमला हुआ, ट्रम्प ने उसका मखौल उड़ाया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े की तैनाती है, जिसमें लगभग 9,000 सैन्य कर्मी और नागरिक कर्मचारी शामिल हैं। इराक में लगभग 2,500 अमेरिकी सैनिक हैं। 3 जनवरी, 2020 को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के प्रतिशोध में अल–असद और एरबिल अमेरिकी बेस को ईरान ने निशाना बनाया था। वर्ष 2023 से ईरान समर्थित हौथी आतंकवादी समूह लाल सागर और अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले कर रहे हैं, जिसमें अमेरिकी जहाजों पर हमले भी शामिल हैं। इराक में तेहरान समर्थित शिया मिलिशिया, हिजबुल्लाह अलग से एक्टिव हैं। तो क्या ट्रम्प के 'सीज फायर' बोल भर देने से बंदूकें गरजनी बंद हो जायेंगी? इस सच से अमेरिकन्स और इस्राइली वाकिफ हैं कि अकेला ईरान है, जिसके 'हमास', 'हिज़बुल्लाह', 'इस्लामिक जिहाद' जैसे प्रॉक्सी मिलिटेंट्स, पूरे मिडल ईस्ट में पसरे हुए हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रमुख 'स्विंग स्टेट' कूटनीतिक समाधान की कोशिश में हैं। सऊदी अरब, मिस्र, इराक, जॉर्डन सहित अधिकांश अरब राज्यों ने ईरान पर इस्राइल के हमलों की निंदा की है, ताकि तेहरान को इन पर भरोसा हो। ट्रम्प ने ऐसी प्रतिक्रिया सोची नहीं थी। युद्धविराम की तत्काल घोषणा की सबसे बड़ी वजह यह भी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रतिनिधि हुसैन शरीयतमादारी ने कट्टरपंथी कायहान अखबार से कहा, 'अब हमारी बारी है। हम बिना समय बर्बाद किए, अमेरिकी, ब्रिटिश, जर्मन और फ्रांसीसी जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह बंद करेंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य के बरास्ते, वैश्विक तेल और गैस का पांचवां हिस्सा दुनियाभर को सप्लाई होता है, यह यदि बंद हुआ, तो विकल्प क्या है? सबसे व्यवहार्य विकल्प सऊदी अरब के बरास्ते ईस्ट–वेस्ट पेट्रो पाइपलाइन है, जो लाल सागर तक तेल पहुंचा सकती है। अन्य विकल्पों में इराक पाइपलाइन (आईपीएसए) और ओमान की खाड़ी में फुजैराह से जोड़ने वाली पाइपलाइनें शामिल हैं। यूरोपीय नेताओं की भृकुटियां इससे तन गई हैं। उन्हें लगता है, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को गद्दी से उतार देना अंतिम उपाय है। दरअसल, अमेरिकी हमलों ने एक बार फिर से अयातुल्ला अली खामेनेई की जड़ों को मजबूत कर दिया है। ईरान की नई पीढ़ी उनकी रूढ़िवादी और बुर्कापरस्त नीतियों का विरोध कर रही थी। जो युवा तेहरान की सड़कों पर सर्वोच्च नेता के खिलाफ मुट्ठी तानकर खड़े थे, वही चेहरे खामेनेई के समर्थन में खड़े हैं। बिना पब्लिक सपोर्ट के सत्ता परिवर्तन आसान नहीं है, इस सच को अमेरिकंस भी समझते हैं। यूरोपीय शक्तियां पहले ईरान के साथ यूरेनियम संवर्धन रोकने, अपने मिसाइल कार्यक्रम पर लगाम लगाने, और प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देना बंद करने के लिए एक समझौते पर दबाव डाल रही थीं। लेकिन ईरान ने पूर्ण रोक को अस्वीकार कर दिया है, कि उसका संवर्धन शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यूरोपीय–अमेरिकन नेता भूल जाते हैं, कि पुतिन और शी पूरी खामोशी से इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने क्रेमलिन में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से सोमवार को मुलाकात की, और अमेरिकी हमले की भर्त्सना की। उत्तर कोरिया ने भी लगे हाथ ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की है, और इसे संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन बताया। इसके मायने क्या निकलते हैं? उत्तर कोरिया, ईरान के मिसाइल कार्यक्रमों का अहम सहकार है। ट्रम्प को पता है, मास्को–चीन–उत्तर कोरिया धुरी ईरान में एक्टिव हो चुकी है। मार्च, 2023 में पेइचिंग समझौते के बाद से, सऊदी–ईरान संबंधों ने नए अध्याय में प्रवेश किया है। उभयपक्षीय भरोसे की वजह से सऊदी अरब में फंसे 70 हजार से अधिक ईरानी हज यात्रियों को किंगडम ने आश्रय, चिकित्सीय देखभाल, और परिवहन प्रदान किया। एक बात तो मानकर चलिए, मिडल–ईस्ट में कूटनीति निकट भविष्य के लिए मर चुकी है। अमेरिका–इस्राइल की कोशिश, सद्दाम हुसैन, कर्नल गद्दाफी की कहानी दोहराने की होगी। ट्रंप ने 17 जून को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये अयातुल्ला अली खामेनेई का नाम लेते हुए लिखा,

कड़वाहट से मुक्ति के लिये सम्मानजनक अलगाव

डॉ. सुधीर

आज के बदलते सामाजिक परिवेश में, जहां रिश्ते जटिल होते जा रहे हैं, तलाक एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। भारत में तलाक की प्रक्रिया अक्सर लंबी, तनावपूर्ण और आरोप–प्रत्यारोप से भरी होती है। यह न केवल पति–पत्नी बल्कि उनके बच्चों और परिवारों के लिए भी भावनात्मक और आर्थिक बोझ बन जाती है। पारंपरिक तलाक कानूनों में, तलाक तभी दिया जाता है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष पर 'गलती' (जैसे व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग) साबित करे। इसमें अक्सर एक लंबी और थकाऊ कानूनी लड़ाई शामिल होती है, जिसमें दोनों पक्षों को एक–दूसरे पर आरोप लगाने पड़ते हैं, जिससे कड़वाहट और दुश्मनी बढ़ती है। इसके विपरीत, 'नो–फॉल्ट' तलाक में, तलाक के लिए किसी भी पक्ष को दूसरे की गलती साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें बेवफाई, क्रूरता या परित्याग जैसे विशिष्ट कारणों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है और सुलह की कोई संभावना नहीं है, तो दोनों पक्षों को सम्मानपूर्वक अलग होने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका मुख्य आधार 'अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका विवाह' होता है। ऐसे में, विकसित देशों के अनुभवों से सीखना महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां 'नो–फॉल्ट' तलाक एक सफल मॉडल साबित हुआ है। विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में 'नो–फॉल्ट' तलाक ने कई सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। सबसे पहले, इसने तलाक की प्रक्रिया को काफी सरल और तेज बना दिया है। अदालती कार्यवाही कम होती है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। दूसरा, यह प्रक्रिया को कम विरोधी बनाता है। जब किसी एक पक्ष पर दोष नहीं लगाया जाता, तो कटुता और प्रतिशोध की भावना कम होती है, जिससे बच्चों के लिए बेहतर माहौल बनता है और भविष्य में सह–पालन की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, यह महिलाओं को सशक्त बनाता है। पारंपरिक तलाक कानूनों में अक्सर महिलाओं को अपनी स्थिति साबित करने के लिए अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता था, लेकिन 'नो–फॉल्ट' तलाक उन्हें इस बोझ से मुक्त करता है। भारत में वर्तमान में तलाक के लिए विभिन्न आधार उपलब्ध हैं और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत आपसी सहमति से तलाक (धारा 13 बी) शामिल हैं। आपसी सहमति से तलाक 'नो–फॉल्ट' सिद्धांत के करीब है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें और प्रतीक्षा अवधि शामिल है। भारत में तलाक से संबंधित मौजूदा कानून, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, अभी भी काफी हद तक 'फॉल्ट–आधारित' है। जबकि आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान है, यह तभी संभव है जब दोनों पक्ष सहमत हों और एक निश्चित अवधि तक अलग रह चुके हों। लेकिन अगर एक पक्ष तलाक नहीं चाहता, तो दूसरे पक्ष को क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग या मानसिक बीमारी जैसे आधारों पर दोष साबित करना पड़ता है। यह प्रक्रिया अक्सर अपमानजनक और लंबी खींचने वाली होती है, जिससे दोनों पक्षों को मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचता है। शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023) का मामला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस महत्वपूर्ण मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'अपरिवर्तनीय वैवाहिक विच्छेद' के आधार पर सीधे तलाक को मंजूरी दी। यह निर्णय इस मायने में उल्लेखनीय था कि यह ऐसे समय में आया जब तलाक के लिए कानून में 'अपरिवर्तनीय वैवाहिक विच्छेद' का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को 'नो–फॉल्ट' सिद्धांत की दिशा में एक बड़ा और प्रगतिशील कदम माना गया।

..... विविध .....

चेहरे की झाइयों को जड़ से मिटाए, बस 5 रुपए का होगा खर्चा

चेहरे पर दिखने वाली झाइयों को अक्सर लोग बढ़ती उम्र का असर मानकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये झाइयां सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि हमारी लापरवाही का नतीजा भी होती हैं? हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या, खराब खानपान और सबसे ज्यादा गड़बड़ नींद का शेड्यूल झाइयों की बड़ी वजह हैं। जब चेहरे पर ये गहरे निशान बनने लगते हैं तो चेहरा अपनी उम्र से बड़ा और थका हुआ नजर आता है। ऐसे में अक्सर लोग महंगी क्रीम्स और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं। लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। अगर आप झाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं और साथ ही अपने चेहरे को नुकसान से भी बचाना चाहते हैं, तो एक आसान घरेलू उपाय को आजमा सकते हैं।

इंस्टाग्राम से मिला असरदार नुस्खा

इस घरेलू उपाय को मशहूर कंटेंट क्रिएटर दशमेश राव ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में साझा किया है। उन्होंने बताया कि ये नुस्खा बेहद आसान और सस्ता है। इसे बनाने में सिर्फ 5 रुपये का खर्च आता है। और अगर आप इसे 7 दिन तक रोज इस्तेमाल करते हैं, तो झाइयां साफ हो जाएंगी और स्किन बिल्कुल बेबी सॉफ्ट नजर आएगी।

किन चीजों की जरूरत होगी?

सामग्रीरू 2 आलू, थोड़ा पानी, एलोवेरा जेल, एक चुटकी हल्दी, 1 विटामिन–ई कैप्सूल (सामग्री की मात्रा चेहरे की जरूरत के हिसाब से कम–ज्यादा कर सकते हैं)

टपमू जीपे चवेज वद प्देजंहतंउ

इस नुस्खे को कैसे बनाएं?

सबसे पहले दो आलू को छीलकर टुकड़ों में काट लें।

इन टुकड़ों को मिक्सी में डालें और थोड़ा सा पानी मिलाएं।

अब इनको अच्छी तरह पीस लें और रस निकाल लें।

जूस को एक कटोरी में निकालकर 10 मिनट तक छोड़ दें।

अब आप देखेंगे कि नीचे सफेद स्टार्च जम गया है कृ बस इसी स्टार्च का इस्तेमाल करना है।

इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल, एक चुटकी हल्दी, और 1 विटामिन–ई कैप्सूल का तेल मिलाएं।

इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें।

आपकी झाइयों के लिए खास घरेलू फेस मास्क तैयार है।

इसे कैसे लगाएं?

रात को सोने से पहले चेहरे को साफ करें।

अब इस तैयार मास्क को चेहरे पर लगाएं और पूरी रात इसे ऐसे ही छोड़ दें।

अगली सुबह उठकर चेहरा धो लें।

अगर आप इसे लगातार 7 दिन तक करते हैं, तो चेहरे की झाइयां हल्की होने लगेंगी और त्वचा साफ, मुलायम और ग्लोइंग हो जाएगी।

झाइयों के पीछे क्या कारण होते हैं?

धूप में ज़्यादा समय बिताना

नींद पूरी न होना

पोषण की कमी

हार्मोनल बदलाव

तनाव और स्किन की सही देखभाल न करना

क्यों असरदार है आलू का रस?

आलू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण होते हैं। यह पिगमेंटेशन, टैनिंग और मुंहासों के दाग को हल्का करता है।

इसमें मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को पोषण देते हैं।

पेट में आई हल्की सी गांठ को न करें अनदेखा तुरंत कराएं टेस्ट

अगर कभी आप कपड़े बदलते समय या नहाते वक्त पेट पर हल्की सी उभरी हुई गांठ महसूस करें, तो उसे नजरअंदाज न करें। हो सकता है वो गांठ सामान्य हो, लेकिन कुछ मामलों में यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। यह खबर इसी विषय पर आधारित हैजानिए पेट में गांठ क्यों बनती है, इसके लक्षण क्या हैं और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।

पेट में गांठ बनने के मुख्य कारण

हर्निया

यह सबसे सामान्य कारण होता है। जब पेट की अंदरूनी दीवार कमजोर हो जाती है और आंत का कोई हिस्सा बाहर की ओर निकल आता है, तो गांठ बन जाती है। खड़े होने या खांसने पर यह गांठ और उभरी दिखती है।

लिपोमा

यह एक नरम और बिना दर्द की गांठ होती है जो फैट से बनती है। यह खतरनाक नहीं होती, लेकिन धीरे–धीरे इसका आकार बढ़ सकता है।

सिस्ट (ब्लेज)

सिस्ट ऐसी गांठ होती है जो तरल या अर्ध–ठोस पदार्थ से भरी होती है। यह त्वचा के नीचे बनती है और कभी–कभी सूजन या हल्का दर्द दे सकती है।

इंफेक्शन या सूजन

कभी–कभी त्वचा के नीचे बैक्टीरियल संक्रमण या लिम्फ नोड्स में सूजन के कारण भी गांठ बन जाती है। यह गांठ छूने पर गर्म और दर्दनाक महसूस हो सकती है।

ट्यूमर या कैंसर

हालांकि ऐसा कम होता है, लेकिन अगर गांठ धीरे–धीरे बढ़ रही है, सख्त है और दर्द नहीं कर रही, तो यह किसी ट्यूमर या कैंसर का संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है।

पेट में गांठ का इलाज

पेट में गांठ का इलाज उसकी वजह पर निर्भर करता है। अगर गांठ हर्निया के कारण है, तो आमतौर पर सर्जरी की जरूरत होती है। लिपोमा जैसी फैट वाली गांठ अगर दर्द नहीं देती तो इलाज जरूरी नहीं होता, लेकिन परेशानी होने पर इसे सर्जरी से हटाया जा सकता है। सिस्ट (ब्लेज) यदि छोटी है तो डॉक्टर केवल निगरानी में रख सकते हैं, लेकिन बड़ी या संक्रमित होने पर एंटीबायोटिक और सर्जिकल रिमूवल की सलाह दी जाती है। अगर गांठ किसी इंफेक्शन या लिम्फ नोड्स की सूजन के कारण बनी है, तो एंटीबायोटिक से इलाज किया जाता है। वहीं, गांठ ट्यूमर या कैंसर का संकेत हो तो डॉक्टर बायोप्सी, स्कैन और फिर कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी जैसी विशेष उपचार विधियां अपनाते हैं।

कब सतर्क होना जरूरी है? (खतरे की घंटी)

अगर आपकी पेट में बनी गांठ में नीचे दिए गए लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें–

गांठ का धीरे–धीरे बड़ा होना। बिना दर्द की लेकिन सख्त गांठ। गांठ की त्वचा का रंग बदल जाना बुखार रहना या अचानक वजन कम होना। गांठ में जलन, पस या मरोड़ महसूस होना। पेट में उभरी गांठ हमेशा खतरे की बात नहीं होती, लेकिन यह किसी बड़ी बीमारी की शुरुआत भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि शरीर में हुए किसी भी बदलाव को हल्के में न लें। यदि कोई गांठ महसूस हो, तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। समय पर पहचान और इलाज से बड़ी परेशानी टाली जा सकती है।

पेट दर्द को न समझें गैस या एसिडिटी, ये हो सकते हैं गंभीर रोगों के लक्षण

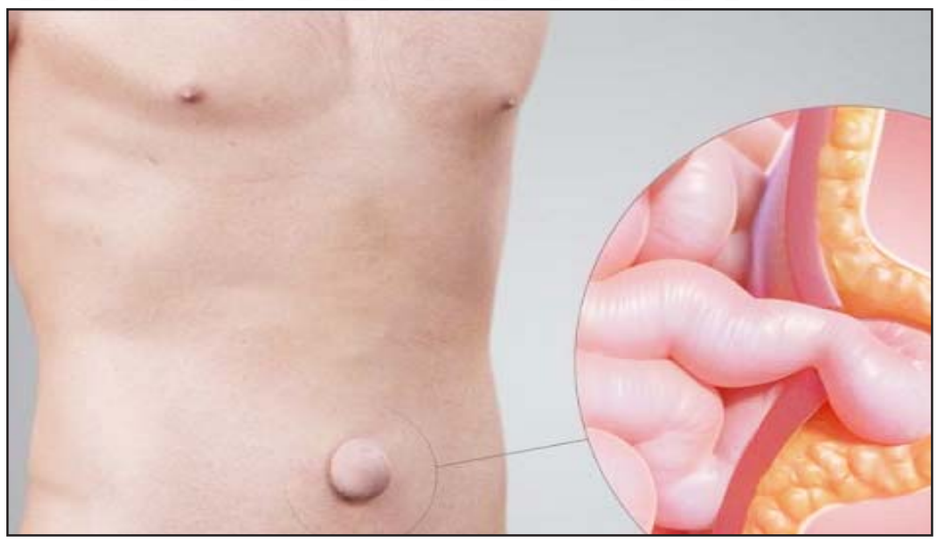

पेट दर्द एक आम समस्या है, लेकिन हर पेट दर्द सामान्य नहीं होता। अगर आपके पेट में खासकर दाएं ऊपरी हिस्से या नाभि के आसपास लगातार या तीव्र दर्द हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। यह एक गंभीर बीमारी दृ अपेंडिसाइटिस गॉलब्लैडर स्टोन या फिर लिवर से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। हालांकि ज्यादातर लोग पेट दर्द को गैस, अपच या एसिडिटी समझकर घरेलू इलाज में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर स्थिति में बदल सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक, अगर दर्द एक निश्चित जगह पर केंद्रित है, तेज होता जा रहा है और इसके साथ बुखार, उल्टी, या भूख न लगने जैसे लक्षण जुड़ते हैं, तो यह एमरजेंसी की स्थिति हो सकती है। पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में दर्द क्यों होता है?

पेट का दाहिना ऊपरी हिस्सा, यानी राइट अपर एब्डोमिनल एरिया, शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों का स्थान होता है। यहां स्थित होते हैंरू

लिवर (यकृत)

गॉलब्लैडर (पित्ताशय)

छोटी आंत का हिस्सा

डायाफ्राम के नीचे का भाग

इस क्षेत्र में दर्द होने का मतलब है कि इनमें से किसी एक अंग में समस्या हो सकती है। यह दर्द किन बीमारियों का संकेत हो सकता है?

गॉलब्लैडर स्टोन (पित्ताशय की पथरी)

यह पेट दर्द के सबसे आम कारणों में से एक है। जब गॉलब्लैडर (पित्ताशय) में पथरी बन जाती है, तो यह विशेष रूप से खाने के बाद दृ खासकर जब भोजन वसायुक्त हो दृ तेज और असहनीय दर्द पैदा कर सकती है। यह दर्द आमतौर पर पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में महसूस होता है और कुछ मामलों में कंधे या पीठ तक फैल सकता है। इसके साथ उल्टी, बदहजमी और हल्का बुखार जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। यदि समय रहते इसका इलाज न हो, तो यह पित्ताशय में सूजन या संक्रमण का कारण बन सकता है।

हिपेटाइटिस या लिवर इंफेक्शन

लिवर से जुड़ी समस्याएं, जैसे वायरल हिपेटाइटिस, भी पेट के दाएं ऊपरी हिस्से में दर्द का कारण बन सकती हैं। जब लिवर में सूजन आती है, तो यह न केवल दर्द उत्पन्न करता है, बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है। इस स्थिति में आंखों और त्वचा का पीला पड़ना (पीलिया), लगातार थकान, मिचलाना और हल्का बुखार आम लक्षण होते हैं। लिवर संक्रमण को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए समय पर जाँच और इलाज आवश्यक है।

अपेंडिसाइटिस

अपेंडिक्स, पेट के दाएं निचले हिस्से में स्थित एक छोटी सी थैली होती है, जिसमें सूजन आ जाए तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इस बीमारी में पेट दर्द आमतौर पर नाभि के आसपास शुरू होता है और धीरे–धीरे दाहिनी ओर खिसक जाता है। दर्द के साथ–साथ भूख न लगना, उल्टी और बुखार जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। अगर इसे समय रहते नहीं पहचाना गया, तो अपेंडिक्स फट सकता है और यह जानलेवा स्थिति बन सकती है।

पीजीआई में नर्सिंग समेत 1397 पदों पर भर्ती शुरू

लखनऊ, (संवाददाता)। संजय गांधी पीजीआई में नर्सिंग समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तारीख 18 जुलाई है। भर्ती संबंधी विस्तृत जानकारी वेबसाइट ्रेहचपउे.वतह.पद पर उपलब्ध है। पीजीआई में नर्सिंग के 1200 पदों के साथ ही कुल 1397 पदों पर भर्ती होनी है। संस्थान की वेबसाइट पर आवेदन का लिंक दे दिया गया है। संस्थान की ओर से जारी विज्ञापन के तहत नर्सिंग के 1200 पदों के साथ ही जूनियर अकाउंट ऑफिसर के छह, टेक्निकल ऑफिसर सीडब्ल्यूएस बायोमेडिकल के एक, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के सात, स्टोर कीपर के 22, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर

ग्रेड–2 के दो, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 32, स्टेनोग्राफर के 64, सीएसएसडी असिस्टेंट के 20, ड्राफ्टमैन के एक और हॉस्पिटल अटेंडेंट के 43 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा। सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क जीएसटी समेत 1180 और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 708 रुपये होगा। अंग्रेजी माध्यम से कंप्यूटर आधारित होगा टेस्ट सभी पदों पर भर्ती कंप्यूटर आध ाारित टेस्ट के आधार पर होगी। भाषा का माध्यम अंग्रेजी रहेगा। ग्रुप–घ के अभ्यर्थियों को इससे छूट मिलेगी। इसका सिलेबस पीजीआई की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा लखनऊ के साथ ही देशभर के चुनिंदा शहरों में होगी।

जिले के अंदर तबादले के लिए 63646 पद उपलब्ध

लखनऊ, (संवाददाता)। परिषदीय विद्यालयों में जिले के अंदर सामान्य तबादलों के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इसके तबादले की भी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत मंगलवार देर शाम विद्यालयों की रिक्तियां जारी की गई हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि प्रदेश के 67048

लिए रिक्तियां जारी कर दीं। इसके तहत प्रदेश के 67048 स्कूलों में 63646 पद उपलब्ध हैं। प्रदेश में शिक्षक–छात्र अनुपात सही करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न कवायद की जा रही है। इसी क्रम में जिले के अंदर सामान्य में 63646 पद उपलब्ध हैं। इनके सापेक्ष तबादले के लिए शिक्षक बुध ावार से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए दो दिन निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत अन्य औपचारिकता पूरी कर शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में सामान्य व परस्पर तबादले की प्रक्रिया पूरी की गई है। इससे शिक्षक–छात्र अनुपात काफी बेहतर करने में सहयोग मिलेगा।

मिशन कर्मयोगी के लिए नोडल नामित

केंद्र सरकार के मिशन कर्मयोगी को गति देने के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बताया कि निदेशालय स्तर पर राज्य परियोजना निदेशक, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राप्ति ाकरण, निदेशक बेसिक व माध्यमिक, एससीईआरटी, सीमेट व अपर शिक्षा निदेशक को नामित किया गया है। इसी तरह बेसिक व माध्यमिक सचिव, एससीईआरटी के कार्यालाध्यक्ष, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व सहायक शिक्षा निदेशक, डायट प्राचार्य, डीआईओएस व बीएसए को नोडल नामित किया गया है।

बारिश से कई पॉश इलाकों में भरा पानी, चोक नालों की वजह से कुछ मोहल्लो के घरों में भी भरा बरसाती जल

लखनऊ, (संवाददाता)। मंगलवार को अलग–अलग इलाकों में रुक–रुक हुई बारिश से गोमतीनगर जैसी पॉश कॉलोनी सहित कई इलाकों में सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी तो हुई ही, घरों में फर्नीचर व अन्य सामान खराब भी हुआ। दोपहर बाद हुई करीब एक घंटे की ही बारिश में अयोध्यादास वार्ड में बड़े दुर्गा मंदिर के पास नाला चोक हो गया, जिससे मंदिर व आसपास के घरों में गंदा पानी भर गया।

अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर शुभांशु ने रचा इतिहास

लखनऊ, (संवाददाता)। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन व भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के माता–पिता अपने बेटे की उपलब्धि पर भावुक हो गए। वो कानपुर रोड स्थित सीएमएस के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। शुभांशु 41 वर्ष पहले लगातार आठ दिन पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में रवाना होने वाले दूसरे भारतीय बने। एक्सिओम–4 मिशन ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर दी है। लॉन्चिंग के दौरान शुभांशु के माता–पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश को उन पर नाज है। इस मौके पर एसआईए इंडिया के अध्यक्ष डॉ. सुब्बा राव पावुलुरी ने कहा, श्हमारे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जा रहे हैं। यह भारत के लिए एक महान दिन है। एक्सिओम मिशन का हिस्सा बने भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। मैं उन्हें और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की मां आशा शुक्ला ने कहा कि यह हमारे और सभी के लिए गर्व का क्षण है। जगह–जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सभी को खुशी है कि इस देश का, इस त्रिवेणी नगर का एक लड़का इतनी ऊंचाई पर पहुंचने जा रहा है। हम उसे अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेज रहे हैं। उसे हमारी बहू का पूरा समर्थन है। उसके बिना यह संभव नहीं हो सकता था। उसने यहां सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि हम उसके मिशन के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम बहुत खुश हैं। हमारा आशीर्वाद उसके साथ है और हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि उसका मिशन अच्छे से पूरा हो। उसके लिए लगाए गए सभी पोस्टर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वह लखनऊ, राज्य और हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है। हमें उस पर गर्व है।

किरायेदार बनकर आया, शादी कर बना मालिक फिर बेटी की हत्या कर दी

लखनऊ, (संवाददाता)। पहले पति की मौत के बाद से रेखा ने बेटी सिमरन के सहारे जिंदगी के सपने बुने थे। मां–बेटी साथ में खुश थीं। जीवन यापन के लिए मकान का कुछ हिस्सा किराये पर दे रखा था। इसी से दोनों का गुजर बसर हो रहा थी। फिर एक दिन विकास चंद्र पांडेय किरायेदार बनकर रेखा के घर में आया। उसके आने के बाद से मां–बेटी की जिंदगी में उथलपुथल मच गई। रेखा ने बताया कि वर्ष 2022 में विकास किराये पर कमरा लेने के लिए आया था। तब वह ई रिक्शा चलाता था। घर में रहने के दौरान विकास मां–बेटी से घुल मिल गया। रेखा की बहन सुनैना के मुताबिक विकास ने रेखा को प्रेम जाल में फंसा लिया, जिसके लिए उन्होंने रेखा को समझाया भी। सुनैना के अनुसार उन्हें शुरू से लगता था कि विकास ठीक आदमी नहीं और उसकी नजर प्रॉपर्टी पर है। हालांकि, रेखा ने विकास से शादी कर ली। इसका सिमरन ने भी विरोध किया। उसे रेखा ने किसी तरह समझा लिया। शादी के बाद विकास घर का मालिक बन बैठा। अन्य किरायेदारों से किराया वसूलना शुरू कर दिया। किराये के रुपयों को लेकर रेखा और विकास से आए दिन झगड़ा होता था। विकास ने मकान में हर जगह कैमरे लगवा दिए थे, जिनसे वह मां–बेटी पर नजर रखता था। वह रेखा व सिमरन पर बंदिशें भी लगाता था। दोनों को जल्दी घर से नहीं निकलने नहीं देता था। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर रेखा का रोकर बुरा हाल था। बिलखते हुए कहा कि जिसपर भरोसा जताया था उसी ने बिटिया की जान ले ली। विकास के मन में सिमरन के प्रति इतनी नफरत थी कि उसने हत्या के बाद 20 से ज्यादा लातें उसके शरीर पर मारीं।

संक्षिप्त खबरें

भातखंडे में तीन संकाय होंगे शुरू

लखनऊ, (संवाददाता)। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में मंगलवार को आयोजित विद्या परिषद की बैठक में शैक्षणिक नीतियों और आगामी योजनाओं को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रो. मांडवी सिंह ने की। बैठक में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पं. बिरजू महाराज एवं बेगम अख्तर की स्मृति में विश्वविद्यालय में तीन विशिष्ट संकाय (पीठ) स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह निर्णय भारतीय संगीत और नृत्य परंपरा के इन महान हस्तियों की स्मृति को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सरोद, सारंगी एवं पखावज जैसे विलुप्त हो रहे पारंपरिक वाद्ययंत्रों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना लागू की जाएगी। इससे इन वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। पद्मभूषण साजन मिश्र ने विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में देशभर के ख्यातिप्राप्त कलाकारों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों–विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। प्रो. उमेश कुमार सक्सेना ने एक सूचना आधारित संग्रहालय की स्थापना का विचार रखा, जबकि सदस्य अरुण भट्ट ने कलाकारों की स्मृति में एक चित्र–वीथिका बनाए जाने की बात कही। प्रो. केके थपलियाल ने शोध विषयों को गंभीर विमर्श के बाद तय करने पर जोर दिया। बैठक में कुलसचिव डॉ. सृष्टि धवन सहित अन्य शिक्षक एवं सदस्य मौजूद रहे।

ईको पर्यटन बढ़ने से होगी स्थानीय लोगों की तरक्की

लखनऊ, (संवाददाता)। तनाव भरे जीवन और अपने काम से संतुलन बनाने के लिए समय निकालकर हमें जंगलों की ओर लौटना होगा। जंगलों में पर्यटन के जरिये प्रकृति की गोद में जाकर हमारी ज्ञानेंद्रियां और चौतन्य होती हैं। ये बातें मंगलवार को सुशांत गोल्फ सिटी में एक निजी होटल में जयबृज जीआरके फाउंडेशन की ओर से वन पर्यावरण और पर्यटन पर हुए सेमिनार में उप्र पर्यटन विभाग के महानिदेशक व प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने कहीं। उन्होंने कहा कि आज यूपी में पर्यटन के अनेक अवसर उपलब्ध हैं, जिसका लाभ युवा पीढ़ी व व्यवसायी ले सकते हैं। जहां भी पर्यटन को बढ़ावा मिलता है वहां चतुर्दिक विकास होता है। वहां के स्थानीय निवासियों के साथ ही साथ अन्य लोगों को भी व्यापार का अवसर मिलता है। हाल में ही संपन्न महाकुंभ इसका शानदार उदाहरण है। सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर प्रमुख वन संरक्षक व उप्र वन निगम के प्रबंध निदेशक केके सिंह ने कहा कि प्रदेश में वन व पर्यावरण के बीच ईको टूरिज्म के तमाम पर्यटन स्थल हैं, जहां जाकर लोग प्राकृतिक वास का आनंद ले रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, कतर्निया घाट टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व में ईको टूरिज्म कार्य प्रगति पर है। जयबृज जीआरके फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार केशव ने कहा कि प्रदेश में इस समय पर्यटन में व्यवसाय के लिए अच्छा माहौल है। कार्यक्रम में उप्र के पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कुमार, उप्र वन निगम के उप प्रबंध निदेशक संजय कुमार, पर्यटन के निदेशक प्रखर मिश्रा, आकाशवाणी के उप निदेशक अजीत कुमार चतुर्वेदी ने भी संबोधित किया।

संक्षिप्त खबरें

गोल चौराहा से कपूरथला चौराहा तक मंदिर मार्ग अंधेरे में

लखनऊ, (संवाददाता)। सीएम ग्रिड योजना में महानगर से कपूरथला चौराहा तक करीब एक किमी के दायरे में सड़क तो चलने लायक बना दी गई है मगर उस पर रात में अंधेरा रहता है। ऐसे में भारी ट्रैफिक वाली इस रोड पर राहगीरों को खतरा रहता है। रोड पर पोल तो डिवाइडर के बीच दो महीने से लगे हैं मगर उन पर लाइटें अब तक नहीं लगाई गई हैं। सीएम ग्रिड योजना के तहत महानगर गोल चौराहा से कपूरथला तक की सड़क पर करीब छह महीने से काम चल रहा है। जिसमें सबसे पहले सड़क के बीच बने डिवाइडर को तोड़ा गया था। जिसमें वहां पर लगे स्ट्रीट लाइट के पोल भी हटाए गए थे। डिवाइडर बनने के बाद स्ट्रीट लाइट के पोल तो लगा दिए मगर उन पर लाइटें नहीं लगाई गईं। जिससे इस सड़क से गुजरने वालों को को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात में दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है। इसको लेकर करीब दो महीने पहले अमर उजाला ने खबर भी प्रमुखता से प्रकाशित की थी। जिसके बाद नगर निगम की ओर से सड़क के दोनों किनारों पर लगे बिजली के पोलों पर कुछ स्ट्रीट लाइटें लगाईं मगर ज्यादातर पर नहीं लगाई है। महानगर गोल चौराहा से मंदिर मार्ग की ओर चलने पर करीब एक किमी के दायरे में महज आठ से दस लाइटें ही एक ओर की पट्टी पर लगी हैं। दूसरी पट्टी पर नहीं लगी हैं। ऐसे में गोल चौराहा से छन्नी लाल चौराहा के पहले तक लगी इन लाइटों से समस्या दूर नहीं हुई। छन्नी लाल चौराहा से कपूरथला चौराहा तक सड़क के दोनों और एक भी लाइट नहीं लगाई गई है। ऐसे में अंधेरा रहता है। गाड़ियों की हेड लाइट से ही सड़क पर रोशनी दिखती है। पूर्व पार्षद शैलेंद्र सिंह बल्लू और सामाजिक कार्यकर्ता सुहैल अहमद ने कहा कि स्ट्रीट लाइटें न होने से लोगों को बहुत समस्या हो रही है। यह जिम्मेदार विभागों की लापरवाही को दर्शाता है।

सहकारिता विभाग का खेल, धरे रह गए 27 करोड़ के माइक्रो एटीएम

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए खरीदे गए करीब 27.96 करोड़ के माइक्रो एटीएम अफसरों की लापरवाही से धरे रह गए। कुछ समितियों में इनका संचालन शुरू जरूर हुआ, लेकिन कई स्थानों पर ये रखे–रखे खराब हो गए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से समितियों को समृद्ध करने और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने की योजना तैयार की गई थी। इसके तहत पैक्स में माइक्रो एटीएम लगाने का फैसला हुआ था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत अक्तूबर 2020 में 7479 पैक्स के लिए 27.96 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया था। कृषि विभाग ने इस धनराशि को सहकारिता विभाग को सौंप दिया। सहकारिता विभाग में उप्र. को–ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध ा निदेशक ने मार्च 2021 में माइक्रो एटीएम खरीदा। विभाग ने दावा किया कि पैक्स पर इन एटीएम को भेज दिया गया है और इनका संचालन शुरू कर दिया गया है। लेकिन, विभागीय जांच में पता चला कि ज्यादातर समितियों को माइक्रो एटीएम मिले ही नहीं। जहां मिले, वहां उनका संचालन नहीं हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर समितियों पर माइक्रो एटीएम रखे रहे और वे खराब हो गए।

लखनऊ के तीन बड़े अस्पताल और सात सीएचसी में जांच का संकट

लखनऊ, (संवाददाता)। राजध ाानी के तीन बड़े अस्पतालों समेत 10 सीएचसी में रेडियोलॉजिस्ट का संकट है। इससे जांच ठप हैं। मरीज निजी केंद्रों पर जा रहे हैं। इसके पीछे गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शासन ने रेडियोलॉजिस्ट की ताजपोशी कर उन्हें अफसर बना दिया। इससे वह प्रशासनिक कार्यों में लग गए और अस्पतालों में मरीजों की जांच का संकट खड़ा हो गया। अफसरों ने फजीहत के बाद अब जिलों में रेडियोलॉजिस्ट का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया है। लखनऊ के तीन बड़े सरकारी अस्पतालों ठाकुरगंज चिकित्सालय, आलमबाग का 50 बेड अस्पताल और बीकेटी के रामसागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय समेत 10 सीएचसी में अल्ट्रासाउंड जांच कई माह से बंद है। मरीजों को अस्पतालों से सिर्फ सलाह देकर जांच के लिए निजी केंद्र का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। हर दिन करीब 100 मरीजों को डॉक्टर दूसरे सरकारी अस्पतालों में भेज रहे हैं, मगर वहां पहले से लोड होने पर मरीजों को मजबूरी में निजी केंद्र जाना पड़ रहा है। हरदोई से बलरामपुर अस्पताल भेजे जा रहे मेडिकोलीगल मामले हरदोई जिला अस्पताल में एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। जांच के लिए मरीज भटक रहे हैं। मेडिकोलीगल मामले में लोगों को लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भेजा जा रहा है। लोगों को मेडिकोलीगल जैसे गंभीर मसले में सौ–सौ किमी की दौड़ लगानी पड़ रही है। सीतापुर सीएमओ के अधीन एक रेडियोलॉजिस्ट काफी समय से तैनात हैं। इन पर भी जांच न करने का आरोप है। ऐसे में अफसरों ने इनका तबादला हरदोई करने की तैयारी की है। अफसरों का कहना है कि इसी माह के आखिर तक व्यवस्था हो जाएगी।

लखनऊ के रेडियोलॉजिस्ट दूसरे जिलों में बने सीएमओ–सीएमएस

शासन ने रेडियोलॉजिस्ट की ताजपोशी कर उन्हें सीएमओ–सीएमएस बना दिया है। इसमें लोकबंधु अस्पताल के सीएमएस भी शामिल हैं। इस कारण वह मरीजों का अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे हैं, जबकि नियम यह है कि प्रशासनिक पद पर कार्यरत अफसरों को हफ्ते में तीन दिन सेवाएं देनी होंगी। वहीं, स्वास्थ्य महानिदेशालय में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉ. संतोष गुप्ता करीब पौने तीन साल से लखीमपुर खीरी के सीएमओ हैं। इसी तरह सिविल अस्पताल में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन चंद्रा को शासन ने बीते साल रायबरेली का सीएमओ बना दिया। अब सिविल अस्पताल में एक ही रेडियोलॉजिस्ट हैं। इस कारण यहां ओपीडी में मरीजों को हफ्ते भर बाद की डेट मिल रही है। इसी तरह सीतापुर जिला अस्पताल के सीएमएस पद पर तैनात डॉ. इंदर सिंह भी रेडियोलॉजिस्ट हैं। स्वास्थ्य महानिदेश डॉ. रतन पाल सिंह के अनुसार जिन जगहों पर रेडियोलॉजिस्ट का संकट है, वहां विशेषज्ञ की तैनाती करने की प्रक्रिया है, ताकि जांच का काम प्रभावित न हो। आसपास के जिलों में तैनात रेडियोलॉजिस्ट को खाली जगहों पर भेजा जाएगा।

ईरान हमलों के खिलाफ फूंका गया अमेरिका और इस्राइल के राष्ट्रपति का पुतला

लखनऊ, (संवाददाता)। ईरान पर हमलों व ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामेनई को दी ध ामकी के खिलाफ छोटा इमामबाड़ा के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इस्राइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू का पोस्टर व झंडा फूंक कर नाराजगी जताई गई। हैदरी टास्क फोर्स की ओर से आयोजित प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि ईरान पर अमेरिका की बमबारी निंदनीय है। हैदरी टास्क फोर्स के अध्यक्ष मुन्ने आगा व महामंत्री जीशान जैदी ने इस्राइल के हमले को इंसानियत पर हमला बताया। भारत को लेकर ट्रंप प्रशासन का दोहरा चरित्र सामने आने लगा है। भारत को भरोसेमंद साथी बताने वाले अमेरिकी विदेश विभाग ने नई चाल चली है। अमेरिका ने भारत में रहने वाले और यहां की यात्रा करने वाले अमेरिकियों के लिए बेतुकी ट्रैवल एडवाइजरी (यात्रा सलाह) जारी की है। भारत को लेवल 2 (अतिरिक्त सावधानी बरतें) श्रेणी में रखकर अमेरिका ने

अपने नागरिकों से कहा है कि भारत में अपराध, आतंकवाद और दुष्कर्म की घटनाओं का जोखिम ज्यादा है। वहीं अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर मेघालय के उपमुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी एडवाइजरी में प्रमुख सुरक्षा खतरे, क्षेत्र के अनुसार यात्रा प्रतिबंध ा और भारत में अमेरिकी नागरिकों के लिए कानून विचार जैसे मुद्दे जोड़े हैं। अधिकारियों ने सिफारिश की है कि महिलाएं अकेले यात्रा करने से बचें तथा विशेष रूप से पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर सतर्क रहें। एडवाइजरी में कहा गया है कि अपराध और आतंकवाद के कारण भारत में अधिक सावधानी बरतें। कुछ क्षेत्रों में जोखिम अधिक है। भारत में हिंसक अपराध और आतंकवाद होते हैं। दुष्कर्म की घटनाएं भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है। यौन उत्पीड़न सहित हिंसक अपराध पर्यटक स्थलों और अन्य स्थानों पर होते हैं।

पारिवारिक फिल्म में दिखेगा हंसी का तड़का

लखनऊ, (संवाददाता)। मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी और अभिनेत्री अदिति राव हैदरी इन दिनों अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए लखनऊ आए हुए हैं। मंगलवार को गोमतीनगर के विभूतिखंड में स्थित एक रेस्टोरेंट में फिल्म के कुछ दृश्य फिल्माए गए। इससे पहले हजरतगंज में भी कुछ दृश्यों का फिल्मांकन हो चुका है। इस फिल्म की शूटिंग इससे पहले उन्नाव में चल रही थी। मंगलवार को ही फिल्म की यूनिट वापस लखनऊ पहुंची। फिल्म के लाइन प्रोड्यूसर दानिश ने बताया कि यह फिल्म पारिवारिक मूल्यों के साथ ही दर्शकों का खूब मनोरंजन भी करेगी। इसमें हंसी का तड़का भी देखने को मिलेगा। फिल्म के निर्माता भानुशील हैं और निर्देशक वरुण शर्मा हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी और अभिनेत्री अदिति राव हैदरी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में बहुत से स्थानीय कलाकारों को भी काम करने का मौका मिला है। मंगलवार को विभूतिखंड के एक रेस्टोरेंट में जहां इस फिल्म के कुछ दृश्य फिल्माए जाने थे, वहां जैसे ही लोगों को पता चला कि पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी फिल्म की शूटिंग करने पहुंचे हैं तो धीरे–धीरे कर भीड़ भी पहुंचने लगी। किसी तरह से बाहर जमा भीड़ को हटाया गया। प्रशंसक पंकज त्रिपाठी की एक झलक पाने को बेकरार दिखे। इससे पहले इस फिल्म की शूटिंग हजरतगंज में भी हो चुकी है जिसमें अदिति और पंकज का रेस्टोरेंट के बाहर का एक सीन शूट किया गया था। विभूतिखंड स्थित शूटिंग स्थल पर अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी और फिल्म की बाकी यूनिट से मुलाकात की। इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय फिल्मों की शूटिंग के लिए बेहतर माहौल बन गया है जिससे मुंबई से बड़े निर्माता–निर्देशक भी लखनऊ समेत अन्य जिलों में फिल्मों की शूटिंग के लिए आकर्षित हो रहे हैं। पंकज त्रिपाठी ने लखनऊ के लोगों के व्यवहार, यहां की तहजीब, जुबान और जायके की भी खूब तारीफ की। डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुविधाएं बहुत अच्छी हुई है जिससे फिल्मकार यहां आने को आतुर हैं।

ऑपरेशन के बाद युवक को जबरन किया डिस्चार्ज, घर पहुंचते ही हुई मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। दुबग्गा स्थित तुलसी हॉस्पिटल में आंत के ऑपरेशन के बाद हुए संक्रमण से सोमवार देर रात मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने मरीज को जबरन छुट्टी देकर पेपर पर साइन करवा लिए थे। वहीं, सीएमओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्नाव के औरास स्थित मवई गांव के रहने वाले विनोद कुमार की मई में तबीयत बिगड़ गई थी। इस पर परिजन उन्हें नजदीकी कुंदन हॉस्पिटल रहीमाबाद ले गए थे। वहां से डॉ. सत्य प्रकाश ने दुबग्गा स्थित तुलसी हॉस्पिटल भेज दिया था, जहां अस्पताल प्रबंधक ने आंत के

ऑपरेशन करने के बदले में साढ़े तीन लाख रुपये वसूल लिए थे। ऑपरेशन के बाद संक्रमण होने से मरीज के टांके सूज गए थे। ऐसे में दोबारा ऑपरेशन किया गया, मगर सूजन खत्म नहीं हुई। तुलसी हॉस्पिटल के संचालक गुरुवेंद्र यादव के अनुसार मरीज के आंत की दोबारा सर्जरी की गई थी। वह चार दिन भर्ती था। उसे डिस्चार्ज किया गया था। इसके बाद तीमारदार मरीज को लेकर घर चले गए थे। लापरवाही का आरोप गलत है। सोमवार को भाई राजेंद्र ने पूरे मामले की शिकायत सीएमओ से की थी। इससे नाराज अस्पताल प्रशासन ने विनोद को जबरन डिस्चार्ज कर दिया। परिजनों के पास इलाज के लिए और रुपये न होने पर वह घर लेकर चले गए। घर पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद विनोद की मौत हो गई। भाई ने अस्पताल प्रशासन पर गलत ऑपरेशन व वसूली का आरोप लगाते हुए शिकायत की है।

मामूली कहासुनी में हुई थी युवक की हत्या - एसपी सिटी

अयोध्या। थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का खुलासा एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में किया।उन्होंने बताया इसमें शामिल आरोपी विनय कुमार प्रजापति पुत्र राममनोरथ प्रजापति निवासी ग्राम पलिया गोवा थाना पूराकलन्दर को गिरफ्तार कर आलाकत्ल, मोबाइल फोन बरामद किया।बताया कि मृतक की हत्या मामूली कहा सुनी के चलते हुई।मृतक नागेन्द्र प्रसाद यादव 23ध 24 जून की रात घर से कुछ दूरी पर रात मे खेत मे पानी लगाने गया था।जिसका शव खेत के पास चारपाई पर मिला था।बताया कि पुलिस ने आरोपी विनय कुमार प्रजापति को ग्राम पलियो गोवा मोड से गिरफ्तार किया।पूछताछ मे आरोपी ने बताया कि उसके गाँव के नागेन्द्र प्रसाद यादव उर्फ सोनू यादव पुत्र रामप्रकाश यादव का खेत मेरे घर से कुछ दूरी पर है।घटना वाले दिन सोनू यादव ने मुझे फोन किया और कहा कि आज कुछ खाया पिया जाय।सोनू मेरे घर से चारपाई लाए थे उसके बाद हम लोग मोतीलाल शाहू के ट्यूबवेल के पास चकरोड पर ही आ गये।आरोपी ने बताया कि वह पुनः चारपाई के पास वापस आ गये थे तब तक सोनू के पडोस के रहने वाले जुग्गीलाल आ गये थे।जिनके साथ सोनू अपने खेत मे पानी देखने चले गये थे।नागेन्द्र प्रसाद यादव लूडो खेले तभी नागेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा मेरी बहन के बारे मे अपशब्दो का प्रयोग करने लगा।मामूली कहासुनी मे रखे हसिया से उसका गर्दन रेत दिया जिससे मौत हो गयी।गिरफ्तार करने वाले टीम मे देवेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पूराकलन्दर,अमरेश त्रिपाठी प्रभारी सर्विलांस टीम,उ0नि0 शशांक कुमार पाठक थाना पूराकलन्दर सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

शासन के निर्देश पर कम संख्या वाले 573 विद्यालयों का होगा समायोजन

समायोजन से ना घबराए छात्रों के अभिभावक - बीएसए

अयोध्या। शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग में जिले के ऐसे 573 विद्यालयों को समायोजन करने के लिए चिन्हित किया है जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम है।इस संबंध में बीएसए अवनीश कुमार पांडेय ने बताया कि जिले मे 458 ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जहां पर 50 से कम छात्र अध्यनरत है।इसके अलावा 115 विद्यालय ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर छात्रों की संख्या 30 से कम है।बताया कि शासन के निर्देश पर शीघ्र ही जिले मे 50 तथा 30 से कम छात्र संख्या वाले 573 विद्यालयों की सूची समायोजन करने के लिए मुख्यालय को भेज दी जाएगी।बताया कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के माता–पिता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।उस स्कूल के 500 मीटर 600 मीटर 800 मी या फिर 1 किलोमीटर पर स्थित विद्यालयों में उनके भी बच्चों का नाम लिखा जाएगा।जहां पर उनके बच्चों के शारीरिक मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाएगा।उन्होंने इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में भ्रमणशील होकर वहां की जनप्रतिनिधियों के साथ आपसी सामंजस बनाते हुए छात्रों के अभिभावकों को विश्वास दिलाए कि शासन द्वारा विद्यालयों के समायोजन को लेकर चिंतित ना हो। उन्होंने छात्रों के अभिभावकों से अपील किया कि आने वाले दिनों में उनके बच्चों मे शिक्षा के साथ–साथ चौमुखी विकास के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कई आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।जिससे कि इन स्कूलों मे शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की नीव मजबूत हो और आगे चलकर देश के अच्छे नागरिक बने।

10 सीटर अत्याधुनिक शौचालय नगर वासियों को समर्पित,महापौर ने फीता काटकर किया लोकार्पण

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। नाका बाईपास चौराहे के ओवर ब्रिज के नीचे 25 लाख रुपये की लागत से निर्मित 10 सीटर सुलभ शौचालय का लोकार्पण महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने फीता काटकर किया।इस शौचालय का निर्माण नगर निगम ने स्वयंसेवी संस्था लाडली फाउंडेशन के तत्वावधान में कराया है।इस मौके पर पार्षद विकास कुमार एवं सूर्यकुमार तिवारी,अपर आयुक्त वागीश कुमार शुक्ल एवं नागेंद्र नाथ, सफाई निरीक्षक राजेश वर्मा, लाडली

फाउंडेशन के आकाश सिंह, भाजपा नेता रमेश राना आदि मौजूद थे। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडे ने बताया कि इस शौचालय में पांच–पांच सीट महिला और पुरुष के लिए अलग–अलग हिस्से में लगाई गई है। इसे प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए ढाई लाख रुपये की अत्याधुनिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है, जो अयोध्या में पहली बार किसी पब्लिक टॉयलेट में लगाया गया है।यह डिवाइस मीथेन गैस को नियंत्रित करेगी। फर्श की सफाई के लिए ऑटोमेटिक क्लीनर लगाया गया है। महापौर ने इस मौके पर शौचालय के सामने बनाए जा रहे पार्क का नाम लाडली वाटिका करने की मांग को स्वीकार किया और पांच बेंच आने वाले लोगों के बैठने के लिए पार्क में लगवाने का ऐलान किया।

दस्तक,संचारी रोग व स्टाप डायरिया रोग को लेकर बैठक संपन्न खत्म स्टॉप

अयोध्या।1 जुलाई से आरंभ हो रहे दस्तक,संचारी रोग अभियान व स्टाप डायरिया 16 जून 25 से प्रारंभ होकर 31 जुलाई 2025 को समाप्त होगा।इसके तहत गुरुवार को बेसिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकोंध्नोडल शिक्षकों का एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,मसौधा पर सम्पन्न हुआ।कार्यक्रम के दौरान नोडल बेसिक अमिताभ सिंह द्वारा संचारी रोगों से बचाव, कारण,वाहक एवम सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया।बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉ प्रदीप कुमार हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर ब्लॉक मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर धीरेंद्र नाथ पांडेय यूनिसेफ ब्लॉक मसौधा के साथ विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व नोडल शिक्षकधशिक्षिकाएं मौजूद रही।बैठक मे उपस्थित शिक्षकों से आगामी 1 जुलाई से निर्धारित शिड्यूल के अनुसार कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित करने की अपील की गईं।यूजर कोऑर्डिनेटर धीरेंद्र नाथ पांडेय द्वारा बताया गया कि जो ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस कंपोजिट विद्यालय पर आयोजित किया जाता है वहां पर हेल्थ वर्कर को एक कमरा या बरामदा उपलब्ध कराया जाए।नोडल टीचर द्वारा जिससे पैदाइशी से 5 साल तक के बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीके और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को उनकी जांच सुगमता से किया जा सके।

जमीनी विवाद में दो सगी बहनों के हत्यारे पति पत्नी को आजीवन कारावास

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर जमीनी विवाद के मामले में दो सगी बहनों की जघन्य हत्या के मामले में एडीजे द्वितीय कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सिकरारा थाना अंतर्गत वादी जतिन पांडेय ने 18/11/21 को थाने पर लिखित शिकायत दिया कि उनके पट्टीदार आशीष पांडेय व ममता पांडेय ने पैतृक जमीन में बिना बटवारा किए शौचालय का निर्माण करवा रहे थे, जिसका उसने व उसकी बहनों पूर्णिमा व अंतिमा ने विरोध किया तो अचानक पति पत्नी आशीष पांडेय और ममता पांडेय ने उत्तेजित होकर बांका और फावड़े से उनकी सगी बहनों को जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया जिससे दोनो बहनों की मौत हो गयी।उक्त घटना में दो अन्य आरोपी रमा शंकर पांडेय तथा सभाजीत हरिजन भी जो विवेचना के दौरान इस घटना में शामिल होने की पुष्टि हुई थी।इन दोनों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने बताया ट्रायल के दौरान कुल 11 गवाह पेस किये गए थे।इन गवाहों के बयान पर एडीजे द्वितीय ने सुनवाई करते हुए आज गुरुवार को आरोपी आशीष पांडेय और उनकी पत्नी ममता पांडेय को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।साथ ही विवेचना में शामिल किए गए दो अन्य अभियुक्त जिनको की साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।उनके खिलाफ भी पत्रावली का निरीक्षण करके अग्रिम विधिक कार्यवाही के लिए तैयारी की जाएगी।

छत से गिरकर युवक की मौत

गड़वार (बलिया) थाना क्षेत्र के सरयां गांव में छत से गिरकर एक युवक की मौत हो गई।जिससे स्वजनों सहित पूरे गांव में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बलिया भेज दिया। बुधवार की रात में सरयां गांव निवासी राहुल गुप्ता (30)वर्ष पुत्र स्व. सुरेश गुप्ता छत पर सोया था। आधी रात में लघुशंका के लिए अंधेरे में छत के किनारे चला गया। अचानक पैर फिसलने के कारण नीचे गिर पड़ा। आवाज सुनकर स्वजन पहुंचे और तत्काल निजी साधन से जिला अस्पताल ले गए जहां जांचोपरान्त चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृत युवक परिवार के साथ कोलकता में रहकर अपना निजी

व्यवसाय करता था।करीब दो सप्ताह पूर्व अपने दादा एवं मां को लेकर गांव आया था।मृतक की पत्नी घटना को सुनकर दो छोटे बच्चों को लेकर कोलकता से आननफानन में गांव के लिए चल दी।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जन जागरूकता कार्यक्रम

देश की उपासना
पत्रकार धनन्जय विश्वकर्मा

जौनपुर। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में 26 जून, 2025 को ष्नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवसष् पर एक जन जागरूकता कार्यक्रम का

आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रधानाचार्या प्रो. डॉ. रुचिरा सेठी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. डॉ. ए. ए. जाफरी के मार्गदर्शन में मानसिक रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विनोद वर्मा द्वारा आयोजित किया गया था।

नशा समाज और राष्ट्र के लिए खतरा

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रधानाचार्या प्रो. डॉ. रुचिरा सेठी ने अपने संबोधन में कहा कि नशीली दवाओं का सेवन और उनकी तस्करी सिर्फ व्यक्ति के जीवन को ही नहीं बर्बाद करती, बल्कि यह पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी बाधा डालती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज जब भारत युवाओं की शक्ति पर गर्व करता है, तो यह बेहद जरूरी है कि हम अपने युवा साथियों को नशे की चपेट में आने से बचाएं। डॉ. सेठी ने बताया कि नशा सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पारिवारिक रिश्तों पर भी बुरा असर डालता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि युवा पीढ़ी नशे को फैशन के तौर पर देख रही है, जो उनके जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने सभी को समझाया कि किसी भी प्रकार का नशा समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि समस्याओं की शुरुआत है। उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी नशे के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने आसपास जागरूकता फैलाएं और यदि कोई इस दलदल में फंसा है, तो उसे सही रास्ता दिखाएं।

नशे की लत एक रोग, इलाज संभव

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. डॉ. ए.ए. जाफरी ने बताया कि नशे की लत एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि समय पर पहचान और सहयोग की जरूरत है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में नशा मुक्ति परामर्श, चिकित्सा सुविधाएं और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि यदि वे अपने आसपास किसी को नशे की लत में उलझा हुआ देखें, तो उसे शर्मिंदगी महसूस कराने के बजाय सहारा दें और इलाज के लिए प्रेरित करें। उन्होंने एक ष्नशा मुक्त समाजष बनाने की दिशा में मिलकर काम करने का आग्रह किया और कहा कि इस दिवस को केवल एक तारीख तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे एक आंदोलन के रूप में अपनाया जाए।

अवैध ड्रग तस्करी के खतरे और युवाओं को जागरूक करने की अपील

मानसिक रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विनोद वर्मा ने अवैध ड्रग तस्करी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि अवैध तस्करी के गिरोह सक्रिय होते हैं जो मुख्य रूप से युवा लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। एक बार जो नशे की चपेट में आ जाता है, उसे इस लत से निकालना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अपील की कि हम सभी मिलकर एक ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बने और एक ऐसा भारत बनाए जो नशा मुक्त हो।

तनाव और जिज्ञासा भी नशे का कारण

मानसिक रोग विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉ. राहुल सिंह ने नशे के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि लोग तनाव दूर करने और जिज्ञासा के कारण नशा करने लगते हैं, ।

समाज की रक्षा के लिए शहीद हुई महारानी दुर्गावती

बस्ती, (संवाददाता)। अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा की ओर से मंगलवार को प्रेस क्लब बस्ती सभागार में वीरांगना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया। महारानी की वीरता का बखान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अपनी वीरता से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दी थीं, कभी सिर नहीं झुकाया। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बलराम गोंड व संचालन महामंत्री अमित गोंड ने किया। कार्यक्रम में गोंड समाज के लोगों को अनुसूचित जाति, जन जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का मामला छाया रहा।मुख्य अतिथि गोंड सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य राजेंद्र प्रसाद गोंड रहे। उन्होंने कहा कि समाज की रक्षा के लिए महारानी दुर्गावती शहीद हुई।

अब जिला चिकित्सालय में नि:शुल्क होगा सीटी स्कैन जॉच

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन जॉच कराये जाने हेतु अब किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देय नही होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय चिकित्सालय में रोगियों को नि:शुल्क सिटी स्कैन सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में उक्त सीटी स्कैन जांच हेतु जिला अस्पताल में शुल्क रु0 500 निध ारित था। जिसे अब जनहित में नि:शुल्क कर दिया गया है। इस दौरान मंत्री द्वारा कहा गया कि शासन गरीब, असहाय सहित सभी लोगो को बेहतर चिकित्सकीय सुविध ा उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है। इसी क्रम में गत 23 जून 2025 को जनपद के अमर शहीद उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत रुपए 1.56 करोड़ की लागत से स्थापित 32 स्लाइस सीटी स्कैन की मशीन का लोकार्पण किया गया था। अब जॉच नि:शुल्क हो जाने से गरीब, कमजोर, असहाय लोगो को मदद मिलेगी तथा उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी।

देश के 12 राज्यों और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से राष्ट्रीय शराब बंदी महासम्मेलन में कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकजुट हुए

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ।अंतर्राष्ट्रीय मध निषेध ा दिवस के उपलक्ष्य में शराबबंदी संघर्ष समिति के तत्वाधान में राष्ट्रीय शराबबंदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, पूर्व केंद्र मंत्री भारत सरकार कौशल किशोर, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हरपाल सिंह जग्गी, मनकामेश्वर मंदिर डालीगंज की महंत दिव्या गिरी महाराज, नगर पंचायत देवां बाराबंकी के अध्यक्ष मो हारुन वारसी मुस्लिम स्कॉलर मौलाना सिबते नूरी, बौद्ध भिक्षु भिकू ज्ञान, कार्यक्रम अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री सांसद आरके चौधरी, पश्चिम विध ानसभा के विधायक अरमान खान, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उत्तर प्रदेश अजय राय, वीररस के राष्ट्रीय कवि वेदव्रत वाजपेई के साथ–साथ सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर शराबबंदी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुर्तजा अली और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने किया उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों और देश के 12 राज्यों से नशाबंदी संघर्ष समिति के साथ जुड़कर अपने–अपने राज्य और जिलों में नशाबंदी के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में एकजुट हुए महासम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री माननीय बृजेश पाठक ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सदियों से लोग जानते हैं कि नशा बुरी लेते हैं लेकिन फिर भी यह बढ़ता जा रहा है इसलिए कि हमने अपने बुजुर्गों की बात को आगे नहीं बढ़ाया शराबबंदी मध निषेध के मुद्दे को मंच से निकालकर हमें आम जनता तक इस मुद्दे को पहुंचना होगा, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा की नशे से लड़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी होगी आज मैं इस राष्ट्रीय शराबबंदी महासम्मेलन में एक मंत्री या नेता के रूप में नहीं बल्कि एक आम इंसान होने के नाते अपना दायित्व निभाने आया हूं, एआइएमआइएम के प्रदेश प्रवक्ता असिम वकार ने अपने अंदाज में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में शराब बंद कर दी गई है मगर उत्तर प्रदेश में अभी तक शराब पर रोक नहीं है जिस तरह छोटे–मोटे चोरों के पैर पर गोली मारी जाती है वैसे ही से अवैध शराब का काम करने वाले लोगों को भी गोली मारी जाना चाहिए,राष्ट्रीय शराबबंदी महासम्मेलन में अतिथियों और 12 राज्यों और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से आए हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुर्तजा अली ने कहा कि पूरी दुनिया नशीली दवाओं की लत के खतरे का सामना कर रही है जिसका असर व्यक्ति परिवार और समाज के एक बड़े हिस्से पर विनाशकारी प्रभाव के रूप में पड़ता है नशा मुक्त जीवन जीने के लिए परिवार और दोस्तों का सहयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है यदि समाज भी इस समस्या के खिलाफ एकजुट हो जाए तो नशे पर काबू पाया जा सकता है नशा मुक्त समाज केवल स्वस्थ ही नहीं बल्कि सशक्त भी होता है हमें इस दिशा में जागरूकता फैलाने और एकजुट होकर काम करने की जरूरत है ताकि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके वही समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने सभी के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि युवाओं और खास करके विद्यार्थियों में नशे की लत बढ़ती जा रही है शराब बंदी संघर्ष समिति इस दिशा में अपना काम कर रही है स्कूल कॉलेज और संस्थानों में जाकर युवाओं को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रही है शराब के प्रयोग को सामान्य व्यवहार के रूप में देखने की बजाये इसे हानिकारक आदत के रूप में देखना चाहिए तथा शराब को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए इसलिए शराब बंदी संघर्ष ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को नशे से मुक्त कर सकता है राष्ट्रीय नशाबंदी महासम्मेलन में होम्योपैथी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ आदर्श त्रिपाठी एवं वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉ राधेश्याम यादव के सहयोग से हैनीमैन चौरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक भव्य निरूशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें नशे की आदत छुड़ाने के लिए निशुल्क दवा वितरित की गई ।

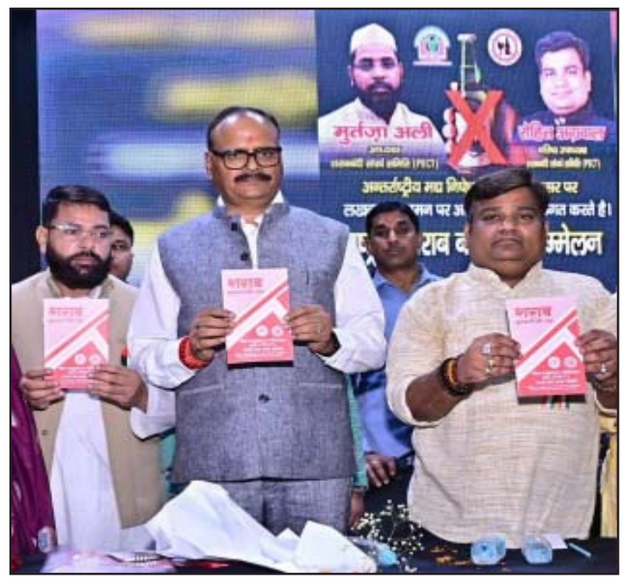

वीसी से हाथापाई में पहले केस खत्म, अब निष्कासन भी निरस्त- 17 छात्र हुए थे निष्कासित

गोरखपुर, (संवाददाता)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जुलाई 2023 में तत्कालीन कुलपति प्रो. राजेश सिंह व कुलसचिव प्रो. अजय सिंह के साथ मारपीट से जुड़े मामले में बड़ी खबर है। डीडीयू प्रशासन ने आरोपी 17 छात्रों का निष्कासन निरस्त कर दिया है। कैंट थाने की तरफ से विवेचना में फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद यह केस कोर्ट में पहले ही खत्म हो चुका है। इसे लेकर डीडीयू में खूब चर्चाएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि डीडीयू के तत्कालीन मुख्य नियंता प्रो. गोपाल प्रसाद ने दो महीने पहले 25 अप्रैल को छात्रों का निष्कासन निरस्त कर दिया था। इससे संबंधित आदेश अब सार्वजनिक हुआ है। तत्कालीन नियंता ने जारी आदेश में कहा है कि 21 जुलाई 2023 को विवि के प्रशासनिक भवन में हुई घटना के संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय की ओर से वाद संख्या 793ध2024 में विवेचक की अंतिम रिपोर्ट एवं वादी के प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने 6 जून 2024 के आदेश के तहत वाद को निरस्त कर दिया गया है। इसके आलोक में कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने 23 अप्रैल 2025 को इन छात्रों का निष्कासन निरस्त किए जाने का आदेश दिया है। इसी क्रम में निष्कासन निरस्त किया जाता है।

इन छात्रों का निष्कासन हुआ निरस्त

मयंक कुमार राय, ऋषभ सिंह, सौरभ गौड़, ओमकार मिश्र, अनुराग मिश्र, शक्ति प्रताप सिंह, शिवम पांडेय, प्रभात राय, सूरज मौर्या, प्रिंस तिवारी, चंद्रपाल सिंह यादव, शुभम गोविंद राव, संजीव त्रिपाठी, प्रतीक रंजन सिंह, पीयूष कुमार, अर्पित कसौधन, दीपक पाण्डेय का निष्कासन निरस्त किया गया है।

यह था मामला

डीडीयू में शुल्क वृद्धि के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। 21 जुलाई 2023 को उनका प्रदर्शन उग्र हो गया था। प्रशासनिक भवन पर प्रदर्शनकारियों ने बिना वार्ता किए निकल रहे तत्कालीन कुलपति प्रो. राजेश सिंह से धक्का–मुक्की करने के साथ ही उनकी गर्दन मरोड़ दी थी। तत्कालीन कुलसचिव प्रो. अजय सिंह को बुरी तरह से पीटा गया था।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।